जांच का विषय है ये मामला, पीड़ितों ने सौंपा ज्ञापन

उजाड़े जा रहे आदिवासियों के घरौंदे

एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए बहेरावासी।

बहेरा के आदिवासी परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को सुनाई अपनी दास्तां।

प्रदेश टुडे संवाददाता, पन्ना

पुश्तों से बसे आदिवासियों जिन्होंने वन अधिकार कानून के अन्तर्गत पट्टे के लिये दिये थे। आवेदन परन्तु उन आवेदनों पर गौर किए बगैर इन बहेरा निवासी आदिवासियों को जबरन वन विभाग द्वारा हटाये जाने से आक्रोशित आदिवासियों ने समाजसेवी यूसुफ बेग के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि यह सभी आदिवासी ग्राम बहेरा तहसील व जिला पन्ना की भूमि पर काबिज हैं व वनों के सहारे व मजदूरी कर अपना जीवकोपार्जन करते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हम परम्परागत अनुसूचित जन जाति के वन वासियों को वनों से खदेड़ा जा रहा है, और बने झोपड़ों को गिराया जा रहा है जिससे हम आदिवासी वन वासियों के घरौंदे तोड़े जा रहे हैं। जिससे इस भीषण ठंड में यह बगैर छत के हो गए हैं और यह अपने बच्चों के साथ ठंड में महिलाओं व बच्चों को लेकर दर दर भटकने को मजबूर हैं। इन सभी आदिवासियों नें वन अधिकार कानून के अंतर्गत पट्टे के लिये आवेदन किया गया है इनके वन अधिकारों को सुलझाए बिना और बिना कोई सूचना दिए वन अमले द्वारा हटाये जाने की कार्रवाई की जा रही है जो सरासर अनुचित है। इस आशय का ज्ञापन कलेक्टर के नाम एसडीएम ओहरे को सौंपा गया। एसडीएम द्वारा जांच का आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों का कहना है मरते दम तक हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे इनका नेतृत्व कर रहे समाजसेवी यूसुफ बेग, एमएल विश्वकर्मा, अनीस खान आदिवासी वनवासी महासंघ एवं समाजसेवी राहुल निगम ने इनकी लड़ाई में साथ देते हुए प्रशासन को आगाह किया गया है अगर इन्हे घर से बेघर किया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे और सभी मिलकर इन आदिवासियों के हक में जिला प्रशासन एवं वन विभाग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने को मजबूर हो जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में सैकड़ों आदिवासी मौजूद थे। इस संबंध में उप वन मण्डल अधिकारी बराछ का कहना था कि फुलवारी गांव से 15-20 परिवार वन कक्ष क्र पी 448 में बहेरा में अवैध रूप से टपरियां बनाकर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। जिन्हें अतिक्रमण करने से रोका गया है न कि उनके घरौंदे उजाड़े गये हैं। क्या यह मामला भी जांच का विषय बनेगा यह तो प्रशासन ही जाने?